for a period from 1-5-1997 to 31-3.2000, on a licence fee payable to AAI at the rate of Rs. 332.75 per sq. m. per month subject to periodical revisions. Directorate of Income Tax has taken over possession of the space and has taken steps to set up an office at the airport. The domestic airport at Delhi will be supervised from the proposed office at Terminal-II of IGI Airport. The Government has plans to set up Air Intelligence Units at other major airpors in the country. At present, such an Unit is functioning at the domestic terminal of he Chennai airport since November, 1993.

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के लिये मानदंड

*296. **श्री अजीत जोगी :**

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण देने में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि लोगों को इस कारण परेशान किया जा रहा है और बैंक अधिकारी आवेदकों से ऋण राशि का दस प्रतिशत कमीशन के रूप में ले रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बैंक शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करते हैं । इस योजना के अन्तर्गत, 18 और 35 वर्ष के बीच के वे व्यक्ति सहायता के लिए पात्र होंगे, जो मैट्रिक पास या फेल हैं या आई.टी.आई. पास हैं या जिन्होंने न्यूनतम छह महीने की अवधि के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी कोर्स किया है और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 24,000/- रुपए से अधिक नहीं है तथा हिताधिकारी के माता-पिता की वार्षिक आय 24,000/- रुपए तक है । आवेदक को कम से कम तीन वर्षों से क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए ।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा पात्र व्यक्तियों से आवेदनों की प्राप्ति, कृतिक बलों द्वारा उसकी संवीक्षा और उसे संबंधित बैंकों को प्रायोजित (स्पांसर) करना शामिल है । तत्पश्चात्, हिताधिकारी द्वारा चयनित व्यापार के आधार पर प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह परामर्श दिया है कि वे ऋण आवेदनों का निर्दिष्ट समय के अन्दर निपटान करें ।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त शिकायतें बैंकों द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्ष की गारंटी की मांग किए जाने, सावधि जमाराशियों का अनुरोध किए जाने, बैंक कर्मचारियों के असहयोग, ऋणों की मंजूरी में अनुचित देरी और अवैध परितोषण की मांग किए जाने जैसे मामलों से संबंधित होती हैं । भारतीय रिजर्व बैंक को जब भी ये शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें आरोपों की जांच करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय / संबंधित बैंक को अग्रेषित कर दिया जाता है । विस्तृत जांच पूरी होने के बाद शिकायतकर्ताओं को मामले की सूचना उपयुक्त रूप दे दी जाती है ।

Single-window scheme for running hotels

*297. SHRI SANJAY NIRUPAM:

SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA':

Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hotel industry is required to get several licences for running the hotels;

(b) if so, whether there is any proposal to have single-window scheme for this purpose;

(c) if so, details thereof; and

(d) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI SRIKANT KUMAR JENA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Do not arise.

(d) The hotel industry is required to obtain a number of licences for running their hotels from the Central and State Government Departments, and other organisations including Municipal Authorities etc. which varry from city to city and State to State.

Removal of milk producs from OGL list

298. SHRI NAGENDRA NATH OJHA:

SHRI JALALUDIN ANSARI:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Dairy Development Board and the National Cooperative Dairy Federation have called upon Government to remove milk products from the list of items imported under Open General Licence;

(b) if so, the details thereof; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULI RAMAIAH): (a) to (c) Yes Sir. National Dairy Development Board (NDDB) and National Cooperative Dairy Federation of India Ltd. have represented to shift import of skimmed milk power and butter oil from free list to restricted list.

As a part of liberalised trade policy, restrictions on import of consumer goods are being removed in a phased manner. At this stage, it will not be desirable to revert an existing freely importable item to the restricted list of import especially in view of the fact that import of butter oil and Skimmed Milk Powder even after they were placed under OGL have not been significant.

NRI Air Taxi services

299. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to permit NRI Air Taxi Service to start its operation on trunk and domestic tourist routes within the country;

(b) if so, the details thereof together with month of effectiveness of such operation;

(c) whether Government also propose to ask this organisation to augment seat capacity for International and National travellers;

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(e) whether some security has been ensured to passengers by this organisation; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C. M. IBRAHIM): (a) No company in the name of NRI Air Taxi Service has applied for permission to operate air transport services in the country.

(b) to (f) Do not arise.

Promotion of Tourism in Orissa

300. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of TOURISM be pleased to state: